अध्यक्ष महोदय : श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : एलैक्शन ला के मातहत वोटर्स को सवारी प्रोवाइड नहीं की जा सकती है । मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि कम से कम महिला वोटर्स के लिए जिन्हें कि धूप में अपने बच्चे को गोदी में उठाये हुए काफी पैदल चल कर कष्ट उठाना पड़ता है उन के लिए सरकार सवारी का प्रबन्ध करे ताकि वह अपने मत का प्रयोग कर सकें ?

श्री मु० यूनुस सलीम : इस तजवीज पर गौर किया जायगा ।

SHRI RANGA : Sometime ago, we learnt from the press that the Election Commission was seriously considering the possibility of organising mobile ballot boxes, so that the ballot boxes would be taken as near the voters as possible and everybody would have an opportunity of votiug. We have not heard anything about it from any of the answers given. This is a suggestion which Rajaji has been making for the past 1½ years. What is happening to that ? Secondly, would Government take the trouble to read the judgments in those election cases in Kashmir and in the light of that, give suitble advice to the Election commission and to the election authorities in Kasmir to ensure that just, proper and impartial conditions are made to prevail during the bye-elections which would be hold there every soon ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE SHRI GOVINDA MENON) : Regarding moblie polling stations what the Elections Commission said was this :

> "All attempts are being made to see that no voter would have to walk more than two miles to a polling booth."

DR. SUSHILA NAYAR : They have to go four and five miles and old men and women can not walk even two miles.

SHRI GOVINDA MENON : I am saying what he said, that all attempts will be made to see that no voter would have to walk more than two miles to reach a polling booth. But where it is not possible and where there are weaker sections of the community like Harijans, those who are prevented by force or who have been subject to coercion and pressure, in such places, the Chief Election Commissioner said that he was contemplating the introduction of mobile polling stations. The other suggestion made by Shri Ranga was in the light of what is stated here regarding Kashmir elections. The Government will bestow consideration on further guarantees to be made in this behalf. Certainly that suggestion will be kept in mind (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : Order, order. The Question Hour is over.

SHORT NOTICE QUESTION

वनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि

\+

SNQ. 9. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री मधु लिमये :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वनस्पति घी निर्माताओं को हाल ही में वनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस वृद्धि से होने वाले प्रभावों पर विचार किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, 8 मार्च, 1969 से । 23 मार्च, 1969 से मूल्य में दोबारा वृद्धि करना आवश्यक हो गया था ।

(ख) पिछले पखवाड़े में वनस्पति तेलों के मूल्य में वृद्धि के कारण ।

(ग) वनस्पति का मूल्य कच्चे तेलों के मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है । कच्चे तेल के मूल्य में यदि कोई बढ़ोतरी अथवा कमी होती है तो उसके अनुसार ही वनस्पति के मूल्य में भी बढ़ोतरी या कमी होती है ।

श्री हरदयाल देवगुण: यह सरकार चुनावों में लाखों रुपये ले कर मिल वालों को मुनाफा पैदा करा रही है और हर सामान्य परिवार पर उस ने कम से कम 5--5 रुपया प्रतिमास का बोझ बढ़ा दिया है । सरकार का कर्त्तव्य है कि वह मूल्यों का स्थिरीकरण करे । लेकिन ऐसा मालूम होता है कि वनस्पति के मामले में यह सरकार नहीं बल्कि सट्टे का चेम्बर है । जिस तरह से चौदह दिन के बाद सौदों का भुगतान होता है सट्टे के चेम्बर में, वैसे ही वनस्पति घी की कीमतें वह तय क ती है । जब हमने इस प्रश्न की सूचना दी थी उस समय उस की कीमत 30 पैसा प्रति किलो बढ़ी थी और जब आप ने प्रश्न को स्वीकार कर लिया उस के बाद वह और भी बढ़ गई ।

इस प्रकार जब चौदह दिन पर कीमतें बढ़नी है तो मिल वाले इस का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं । जैसे ही बाजार में तेल की कीमतें बढ़नी शुरू होती हैं दिल्ली के बाजारों से वनस्पति घी गायब हो जाता है । अभी हाल में यहां के बाजारों में 3-3 और 5-5 रु० टिन के हिसाब से वनस्पति घी में ब्लेक मार्केट होने लगा था ।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को मूंगफली लेवी प्रोक्योरमेंट के तौर हासिल करने की इजाजत दी थी, और क्या गुजरात सरकार ने लेवी के तौर पर मूंगफली हासिल कर रक्खी है ?

दूसरी बात यह है कि कुछ मिलें स्वयं तेल पेरती हैं । औद्योगिक विकास मन्त्री महोदय ने कुछ समय पूर्व उन्हें परामर्श दिया था कि वह डेली क्रशिंग बन्द करें । ऐसी स्थिति में चौदह दिनों के बाद जो कीमतें बढ़ाने का आदेश सरकार दे देती है वह क्यों दे देती है ? क्या यह सच है कि मूंगफली के तेल में सट्टा होता है और सट्टे की वजह से उस की कीमतें चढ़ती हैं और उस की वजह से वनस्पति के दाम बढ़ते हैं ? यदि मूंगफली के तेल का सट्टा होता है तो उसे बन्द करने के लिये क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I would like to submit for the information of the hon. Member that the price of vanaspathi is statutorily fixed. The price of the finished product or vanaspathi is fixed on the basis of the weighted average purchase price of raw oil in the previous fortnight. The Cost Accountants Branch of the Finance Mintstry has worked out certain priniciples on the basis of which the price structure is evolved. Moreover, in order not to leave any doubt in regerd to these matters, we have already referred this matter to the Tariff Commission for examining the cost structure of vanaspathi. As far as the present position is concerned, the supply position is easy. Though a few days earlier there was a report from the Delhi Administration that the supply position was difficult, they have now reported to us that the present availabilty position is easy. So, there is no difficulty as far as vanaspathi coming into the market is concerned.

श्री हरदयाल देवगुण : अध्यक्ष महोदय, मैं ने यह पूछा है कि गुजरात में जो मूंगफली प्रोक्योरमेंट में हासिल की गई थी उस को इन मिलों को एक निश्चित भाव पर बेचने की कोई व्यवस्था है, और उस के फलस्वरूप क्या सरकार यह तय करेगी कि वनस्पति घी की कीमतें छः छः महीने पर तय की जायें बजाय इस के कि चौदह चौदह दिन पर तय करके आप मिल वालों को जमाखोरी करने का मौका दें ? एक बार साल के पहले छः महीने के लिये तय की जाये और दूसरी बार साल के दूसरे छमाही के लिये

तय की जाये। क्या सरकार वर्तमान प्रथा को बदलेगी और छः छः महीने पर कीमत तय करने की प्रथा को चलायेगी ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस इंडस्ट्री में खुला कम्पिटीशन पैदा करने के लिये आम लोगों को इस मैदान में आने की सरकार सुविधा प्रदान करेगी ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : In my view, it may not be practicable to fix the price of the finished product on the basis of the price of the raw material for the previous six months .... As I have said, we have referred this matter to the Tariff Commission. If the Tariff Commission makes a similar recommendation, we will consider it.

श्री मधु लिमये : ऐसा लगता है कि खाद्य मन्त्रालय के पास एक जादू है। वह जिस चीज को छूता है उस का सोना बन जाता है। उन्होंने चीनी को स्पर्श किया दो साल पहले, चीनी सोना हो गई और 5–6 रु० किलो तक उस का दाम हो गया। आज भी उसका दाम 3.50 रु० से अधिक है। इसी तरह से अब की बार उस ने वनस्पति घी को छुआ है और उस का दाम बढ़ने लगा है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मूंगफली और तिलहन की पैदावार को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई है ? दूसरी बात यह है कि मूंगफली और तिलहन के जो दाम बढ़े हैं उनसे किसानों को कितना फायदा हुआ और जो जखीरेबाज अथवा जमाखोर हैं उन को कितना फायदा हुआ ? अगर इस में जमाखोरी को और मुनाफाखोरों को ही फायदा हो रहा है तो क्या सरकार उस के सारे स्टाक को अपने हाथ में ले कर दामों को नियन्त्रित करने का प्रयास करेगी ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I have already submitted that the prices are statutorily controlled. I have also made a further submission that the price structure has been referred to the Tariff Commission for examination. As to the query what is being done by the government to encourage production of groundnut, sesamum oil etc., this can be discussed separately. There is a large number of schemes to encourage the farmers to increase production of groundnuts and the State Government are taking necessary steps. But, last year, due to the failure of the monsoon or erratic behaviour of the monsoon in many areas like Mysore, Andhra Pradesh and Madras, natrually the production of groundnut has received a set-back. We are trying to see that the necessary quantity of soyabeen oil and sun flower oil is imported so that the requirements of the vanaspathi industry is met.

श्री मधु लिमये : मैंने पूछा है कि तेलहन के जो दाम बढ़े हैं उन का फायदा किसानों को मिला या मुनाफाखोरों को ? अगर मुनाफाखोरों को मिला है तो उन के स्टाक को क्यों सरकार अपने कब्जे में न ले ?

MR. SPEAKER : The point is that though production was less because of seasonal conditions, prices had gone down.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : That was in the beginning of the post-harvest period but now the prices have increased. It might be interesting to the hon. Member to know that in the north zone from January 1968 the oil prices increased 22.1 per cent while the price of vanaspati had risen by only 15.1 per cent; similarly, in the south zone the increase in the oil price was to the extent of 18.1 per cent but the vanaspati price rose by 30.5 per cent. As far as raw groundnut prices are concerned, there is no statutory control on groundnut prices.

SHRI K. P. SHINGH DEO : The hon. Minister has been very kind to say that he has referred the question regarding the price structure to the Tariff Commission. But this phenomenon of fluctuation in the price of vanaspati is not of a recent occurrence; it has been occurring sinc 1963. May I know what steps Government had taken in the past, prior to sending it to the Tariff Commission, to see that there was uniformity of price throughout the country and to guard the consumers' interest *vis-a-vis* the increase

in the price of vanaspati ? The statutory control has resulted in fluctuation of price from time to time and the hon. Minister in his-reply has said that within these three months the price has risen thrice, in January as well as in March. May I know categorically as to who is the benefactor–the STC, the speculator or the consumer ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : A number of positive steps had been taken by Government to see that production increases. Ultimately the stability of prices will depend upon easy availability and substantial production. Government has taken positive steps in that direction in that the vanaspati industry has been delicensed; anybody can set up a vanaspati factory now and at least 60 parties have applied for registration for setting up new units. Of course, we have laid down one condition, namely, that monopoly should not develop in this; so, under common ownership management on control we do not allow the total Capacity to exceed 200 tonnes per day.

As far as the price increase is concerned, as I have already explained, this is related to the weighted average price of a fortnight. If there is any charge in the weighted purchase price of raw oil in the previous fortnight, it gets reflected naturally in the next fortnight. There is change from fortnight to fortnight as far as the price is concerned.

SHRI K. P. SINGH DEO : What about the second question ? Who is the benefactor of the fluctuation in the price ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Hon. Members have a doubt that the STC is profiteering out of the imported soyabeen oil and sunflower oil. That is not a correct impression. The STC does issue at the moment soyabean oil at a higher price but may I submit for the information of the hon. Member that a separate fund has been set up and if there is any surplus at any time it goes to that fund or if there is any setback or slump in price, out of this fund the STC is supposed to make up. The surplus amount is not supposed to go to the general profits of the STC. Then, out of this fund some funds are also expected to be spent on giving encouragement to extension activities for increasing the production of groundnut.

SHRI RANGA : have they ever done it ?

श्री कंवर लाल गुप्त : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि वर्षा के अभाव के कारण यह महंगाई वनस्पति घी में हुई है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जहां 1967 में घी का प्रोडक्शन 3 लाख 90 हजार टन हुआ था वहां 1968 में यह बढ़ कर 4 लाख 60 हजार टन हो गया। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन गवर्नमैंट की जो नीति है वह बेसिकली डिफेक्टिव है। वैजीटेबल आयल के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है लेकिन वैजीटेबल घी के ऊपर कंट्रोल है। हर पंद्रह दिन के बाद जब कीमतें बढ़ाई जाती है तो इसका फायदा जो डिसआनेस्ट मैनुफेक्चरर और डिसआनेस्ट ट्रेडर है उसको होता है। वह होर्ड करना शुरू कर देता है और ब्लैक मार्किट में बेचता है। वितरण का जो तरीका है, वह बेसिकली डिफैक्टिव है। अभी श्री देव ने पूछा था कि इसका बैनिफिशरी कौन है ? मैं समझता हूं कि इसका बैनिफिशरी डिसआनेस्ट मैनुफैक्चरर और डिसआनेस्ट ट्रेडर है। दिल्ली में या गाजियाबाद में आप इन्क्वायरी करवा कर देख सकते हैं। बड़े बड़े लोग जिन को इन्होंने पद्मश्री दिया है वे बेईमानी करते हैं, ब्लैक मार्किट करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस डिफैक्टिव पालिसी को देखते हुए क्या सरकार इस पर से कंट्रोल को बिल्कुल खत्म करेगी ताकि कम से कम डिमांड एंड सप्लाई का रूल तो एप्लाई हो ? साथ ही इसके दाम गिरें, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I would make it very clear that Government does not intend to decontrol the price of this commodity. In fact, we have advised the State Governments that under Vanaspati Dealers' Licensing Order, if some

distributors or manufacturers try to exploit the situation, they should take the necessary positive steps so that the consumers' interests are not adversely affected.

As far as production is concerned, production is definitely increasing.

श्री कंवर लाल गुप्त : प्राइस गिराने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I have already replied that it is a controlled commodity.

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH : Is the hon. Minister in a position to assure this House that some day some generation of this country would see the dawning of a day when prices of vanaspati will not rise in spite of the prices of groundnut falling down, when the prices of cloth will not rise in spite of prices of cotton falling down, when prices of agricultural goods will bear some relation somewhere with the industry?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I cannot categorically give an assurance like this because naturally the prices of finished products are dependent on the prices of raw materials. If the prices of raw materials go up, I do not think that it would be possible for us . . . .

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH : My point was that prices of finished products were going up in spite of the prices of raw materials falling down . . . . . *(Interruptions)*

SHRI ANNASAHIB SHINDE : May I complete ? Our intention is to protect the interests of farmers and producers.

श्री जगेश्वर यादव : घी के जो लाइसेंसदार हैं और घी की कीमतें जब गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाई जाती हैं तो क्या उसका एक विशेष यही कारण नहीं है कि इन लाइसेंसदारों से कांग्रेस द्वारा चुनाव के समय में लम्बी लम्बी रकमें ली जाती हैं और उनको उसका मुआवजा देने के लिए इस तरीके से इन कीमतों को बढ़ा दिया जाता है ? क्या इस तरह से जो चन्दा चुनाव के दौरान लिया जाता है, उसको पूर्ति नहीं की जाती है ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I have repeated a number of times that there is complete statutory control over prices and I have also mentioned that we have advised the State Governments that, if in any State some difficulty develops, they should take necessary steps under the law to control distribution.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I want to know from the Minister how they work out the vanaspati prices in such a high rate when the groundnut prices are low; I want to know what is the pattern of working these rates. The import of soyabeen oil will not solve the problem. They have to give support price for the groundnut. They must fix a price and say that if the price goes down, below that, then the State Trading Corporation will purchase. By that action only Government can assure the agriculturists to grow more groundnut, Will the Government, therefore, consider fixing an assured price for groundnut as they fix for vanaspati or paddy ? I want to know when the Government is going to take such a decision and implement it.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I quite appreciate the anxiety of the hon. Member. He is a champion of the cause of groundnut producers. I have discussed with him a number of times and have tried to understand his argument. After discussion with him, we referred the matter to the Agricultural Prices Commission whether statutory minimum prices can be fixed for this commodity. But unfortunately the Agricultural Prices Commission did not agree with this and they have reported to us that it would not be proper at this stage to fix minimum prices.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Scrap that Commission and appoint a new Commission.

SHRI S.M. BANERJEE : The vanaspati manufacturers are so powerful that Government of India want to have congratulations from them. This Government could not find a suitable colour for the last 20 years;

no colour was suitable. In this pattern of rising prices, I would like to know whether they would appoint a Commission to investigate into the cost of production and the selling price–because the difference between the cost of production and the selling price is much–so that the benefit goes to the consumers. I would like to know whether they are prepared to appoint a Commission to investigate into the whole thing.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I am sorry the hon. Member did not properly follow my answers.

SHRI S. M. BANERJEE : You have referred the matter to the Tariff Commission.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Tariff Commission is a competent body which can go into the cost structure.

SHRI S. M. BANERJEE : Why should the price be increased ? Why not you wait for the report of the Tariff Commission ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I do not think there is a need at this stage to refer it to a separate Commission.

श्री रणधीर सिंह : स्पीकर महोदय, इस वनस्पति डालडा ने हिन्दुस्तान के इखलाक को हिन्दुस्तान के चरित्र को भी वनस्पति डालडा बना दिया है। उस में इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स भी आ गये, उसमें लीडर्ज भी आ गये, किसान भी आ गये, मजदूर भी आ गये। मेरा पहला सवाल यह है कि यह फर्क क्यों ? किसान अगर गन्ना पैदा करता है, तो चीनी की कीमत ज्यादा और गन्ने की कीमत कम। कपास पैदा करता है तो कपास की कीमत कम, लेकिन सूत की कीमत ज्यादा। मूंगफली पैदा करता है तो मूंगफली की कीमत कम और सोयाबीन की कीमत ज्यादा। मैं पूछना चाहता हूं कि यह इम्तियाज क्यों ?

दूसरे – क्या आप घी में मिलावट को खत्म करने के लिये डालडा में रंग मिलायेंगे ताकि जो असली घी कह कर बिक रहा है, वह बन्द हो सके। जो डालडा खाना चाहें, वह खायें, लेकिन मिलावट से तो बच सकें ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : इस सरकार में ही मिलावट है। यह सरकार डाल्डा है।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : How to protect the interests of the former producers is engaging constantly the attention of our Ministry and a number of positive steps have been taken.

श्री अब्दुलगनी दार : स्पीकर साहब, जब बदकिस्मती से भगवान नाराज हो गया है, असली घी और दूध मिलता ही नहीं है और डालडा खाना जरूरी हो गया है, तो नेशन की यह डिमाण्ड है कि सरकार एक योजना बनाकर बड़े पैमाने पर वनस्पति घी का कारखाना स्टार्ट करे ताकि जो मुनाफाखोरी आज हो रही है, वह कम हो सके, लोगों को सस्ते दामों पर वनस्पति घी मिल सके। क्या सरकार ऐसा कोई प्रोजेक्ट जारी करेगी ?

[شری عبدالغنی ڈار : سپیکر صاحب- جب بدقسمتی سے بھگوان ناراض ہوگیا ہے-اصلی گھی اور دودھ ملتا ہی نہیں ہے اور ڈالڈا کھانا ضروری ہو گیا ہے- نیشن کی یہ ڈمانڈ ہے کہ سرکار ایک یوجنا بناکر بڑے پیمانے پر وناسپتی گھی کا کارخانا سٹارٹ کرے تاکہ جو منافاکھوری آج ہورہی ہے وہ کم ہوسکے-لوگوں کو سستے داموں پر وناسپتی گھی ملسکے-کیا سرکار ایسا کوئی پروجیکٹ جاری کریگی]

SHRI ANNASAHIB SHINDE: As I have explained, the intention of the Government is that nobody should exploit either the consumers or the producers and take advantage of the situation. That is why

this matter has been referred to the Tariff Commission and that is why statutory control prices were fixed.

श्रीमती जयाबेन शाह : अध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला इतना कम्पलीकेटेड है – कुछ दिन पहले जब ग्राउण्डनट आयल के बारे में चर्चा हुई थी तब भी मैंने बतलाया था – कि वेजिटेबिल घी, सोयाबीन, मूंगफली – ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि वेजिटेबिल की स्टेचूटरी प्राइस मुकर्रिर होती है, लेकिन मूंगफली या मूंगफली के तेल की नहीं होती है – आप यह भी कहते हैं कि बारिश कम हुई है, इस वजह से प्रोडक्शन कम हुआ है, लेकिन मूंगफली के दामों के मुकाबले तेल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ा है। मैं जानना चाहती हूं कि इतना दाम क्यों बढ़ा है ? अगर आप चाहते हैं कि वनस्पति का दाम बढ़े, दूसरी चीजों के दाम बढ़ें तो जरूरी है कि नीचे के दाम भी बढ़ें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारी पालिसी कुछ इस प्रकार की हो रही है कि जब किसान का गल्ला आता है, उस वक्त कोई पालिसी स्टेटमेन्ट नहीं आता है। सोयाबीन के इम्पोर्ट की बात तब हुई जब किसान को ज्यादा दाम मिलने वाला था। इस का नतीजा यह हुआ की कन्ज्यूमर्स और प्रोडयूसर्ज दोनों को फायदा नहीं हुआ। क्या सरकार इन सारी चीजों को देखने के लिये कोई कमेटी बैठायगी ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : A Committee has been appointed to look into these problems.

SHRI SAMAR GUHA : Is it a fact that a set of scientists are of the opinion that hydrogenated vegetable oil which is commonly known as Vanaspati, if continously used by a person, may lead to his blindness. I want to know this. Has this expert opinion been examined by the medical experts of the Government ? If so, what is the report thereto ? If not, I want to know whether Government is going to examine these opinions of this set of scientists ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : From time to time various views are being expressed in regard to this. But so far, the scientists' opinion which is available to the Government goes to indicate that this is not harmful for human body.

MR. SPEAKER : Last supplementary by Shri Sheo Narain.

SHRI SAMAR GUHA : Who are the experts who have given opinion like that ? There are these very important scientists and they have expressed the opinion that it may lead to blindness. I want to know as to who were the authorities who have given this opinion that use of hydrogenated oil will not lead to that type of blindness ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : With due notice I shall be able to give the names.

श्री शिवनारायण : अध्यक्ष महोदय, जयपुर कांग्रेस में यह डिसाइड हुआ था कि कन्ट्रोल हटा दिया जाय। मुल्क भर की यह डिमाण्ड है, कांग्रेस और कांग्रेस से बाहर सब लोगों की डिमाण्ड है कि कन्ट्रोल हटा दिये जांय, जोन्ज़ तोड़ दिये जांय। जब आप कन्ट्रोल लगाते हैं तो जनता को कन्ज्यूमर गुड्स ठीक टाइम पर और ठीक दामों पर नहीं मिलते हैं। क्या सरकार बाटर सिस्टम इन्ट्रोडयूस करेगी, जिससे हम को चीजें मिल सकें ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : There is no difficulty about availability at the moment all over the country.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Misuse of Government Machinery in Hoshiarpur Parliamentary Seat

*693. SHRI SHRI CHAND GOYAL : Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether the Election Commission has received complaints regarding the misuse of Government Machinery in the bye-election of the Hoshiarpur Parliamentary seat in Punjab; and